

मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम (GMVN) लि0 देहरादून द्वारा टौंस नदी लॉट नं-3/10 में लघु लवणों के संग्रहण के लिये पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 26.08.2014 (प्रातः 11.00 बजे) स्थान सैक्टर कार्यालय खनन परियोजना, ग0म0वि0नि0लि0, सुद्धोवाला चौक, सुद्धोवाला, देहरादून का कार्यवृत्त।

मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून द्वारा टौंस नदी लॉट नं-3/10 में लघु लवणों के संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिये जन सुनवाई का आयोजन किया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, अधिसूचना-2006 के अतर्गत आच्छादित है। उक्त परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आख्या, पर्यावरणीय प्रभाव अधिसूचना-1994 यथासंशोधित के अनुसार तैयार की गयी है तथा लोक सुनवाई पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना-2009 के अनुसार की गयी है।

दिनांक 30.06.2014 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), देहरादून श्री प्रताप सिंह शाह, की अध्यक्षता में सैक्टर कार्यालय खनन परियोजना, ग0म0वि0नि0लि0, सुद्धोवाला चौक, सुद्धोवाला, देहरादून में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। राज्य बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में श्री सुभाष पंवार (अ0 अभियन्ता) व श्री सुनील डबराल (अनु0 सहा0) उपस्थित थे।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से 11 बजे प्रातः लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

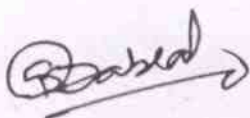
सर्वप्रथम उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि श्री सुभाष पंवार (अ0 अभियन्ता) द्वारा लोक सुनवाई के आयोजन के उद्देश्य के बारे में उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया और कहा गया कि उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून द्वारा टौंस नदी में लघु लवणों के संग्रहण/एकत्रण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। भारत सरकार की अधिसूचना सितम्बर-2006 यथा संशोधित के अनुसार परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई का प्राविधान है। इस हेतु लोक सुनवाई की तिथि से नियमानुसार 30 दिन पूर्व दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला व हिन्दुस्तान टाइम्स के दिनांक 25.07.2014 के अंक में इस आशय की सूचना प्रकाशित की गयी थी। विज्ञप्ति के माध्यम से जन साधारण द्वारा इस परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सुझाव आपत्ति, टीप टिप्पणी आपेक्ष मांगे गये थे। यदि स्थानीय लोगों की परियोजना के बारे में कोई आपत्ति या सुझाव हैं तो उनको इस लोक सुनवाई के माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा, उनके द्वारा जन समुदाय से अनुरोध किया गया कि विचार, सुझाव परियोजना के पक्ष में अथवा विपक्ष में इस मंच के माध्यम से आमंत्रित हैं, जिनकी अनवरत वीडियो रिकार्डिंग एवं फोटोग्राफी भी की जायेगी। मंच के माध्यम से आप सभी के

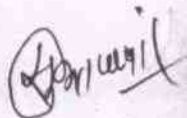
महत्वपूर्ण विचार इस परियोजना के कियान्वयन हेतु एक निर्णायक भूमिका की अभिव्यक्ति होगी।

तदोपरान्त लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह शाह, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन समुदाय से कहा गया कि परियोजना के सम्बन्ध में जो भी आपत्ति एवं सुझाव हैं उन्हें मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करें, जिनको मिनिट्स में सम्मिलित कर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रेषित किया जायेगा।

इस अनुक्रम में मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम के परामर्शी संस्था के प्रतिनिधि श्री विवेक कुमार द्वारा परियोजना से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी दी गयी एवं अवगत कराया गया कि परियोजना का कुल क्षेत्रफल 23.4 है0 है। जो कि ग्राम सुद्धोवाला एवं ईस्ट होपटाउन, तहसील विकास नगर, देहरादून में स्थित है। उक्त परियोजना पूर्णतः सरकारी भूमि पर प्रस्तावित है। जिसे राज्य सरकार द्वारा गढ़वाल मण्डल विकास निगम को लीज पर दिया गया है। परियोजना हेतु किसी प्रकार की निजी भूमि का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य वोल्डर, बालू व बजरी का चुगान/खनन किया जाना है जिनका उपयोग विभिन्न निर्माण कार्यों में किया जायेगा। नदी में लघु लवणों के इकट्ठे होने की वजह से नदी अपना मार्ग बदल देती है, एवं चुगान न होने से बरसात में भूमि कटाव होता है, जिससे कि कृषि योग्य भूमि के साथ-साथ सड़कों/मार्गों को नुकसान पहुँचता है। खनन कार्य को वैज्ञानिक तरीके से किये जाने पर भूमि कटाव की रोकथाम के साथ-साथ स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध होंगे एवं खनिज के दामों में भी कमी आयेगी। परियोजना से लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं राज्य सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस परियोजना से रोजगार को बढ़ावा दिया जायेगा। इस परियोजना में नदी के तटों से 15 प्रतिशत भाग को छोड़कर लघु लवणों का संग्रहण किया जायेगा, उनके द्वारा अपनी प्रस्तुतीकरण में यह भी बताया गया कि 1.5 मीटर गहराई तक रेत, बजरी, बालू का संग्रहण किया जायेगा और संग्रहण कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच किया जायेगा तथा संग्रहण कार्य पूर्णतया मैनुअल किया जायेगा जिसमें कोई हैवी मशीनरी का उपयोग नहीं किया जायेगा। यह परियोजना पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके से की जायेगी। श्री विवेक कुमार द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण में यह भी अवगत कराया गया कि खनन कार्य से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना (ईएमपी) बनायी गयी है, जिसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सड़कों पर जल छिड़काव एवं समय-समय पर वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण कर तदानुसार पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बनायी जायेगी। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुश्रवण हेतु पर्यावरणीय सुरक्षा दल का गठन किया जायेगा। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना हेतु अलग से रू0 5.51 लाख वार्षिक बजट का प्राविधान किया गया है, जिसका उपयोग जल छिड़काव, सड़कों की मरम्मत एवं वृक्षारोपण आदि कार्यों में किया जायेगा।

प्रस्तुतीकरण के बाद परियोजना के सम्बन्ध में जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत सुझावों एवं आपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है-





२

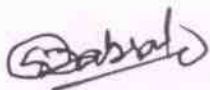
क भूमिका की अभिव्यक्ति

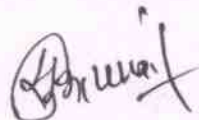
जिलाधिकारी (वित्त)
के परियोजना के
में व्यक्त करें
गयेगा।

तिनिधि
वगत
व

श्री चन्द्रपाल पुण्डीर (पूर्व ब्लॉक प्रमुख, सहसपुर) निवासी सुद्धोवाला द्वारा लोक सुनवाई का स्वागत किया गया एवं खनन कार्य से सहमति व्यक्त की गयी। उनके द्वारा कहा गया कि नदी में खनन बन्द होने से हजारों मजदूर बेरोजगार हो गये हैं, खनन सामग्री की कमी हो गयी है एवं सरकार को राजस्व की हानि भी हो रही है। नदी में खनन न होने से नदी का स्तर बढ़ गया है, जिससे बरसात में बाढ़ से खेत, सड़क आदि का कटाव हो रहा है, जिससे क्षेत्रवासियों को जान माल का खतरा बना रहता है। उनके द्वारा कहा गया कि वन क्षेत्रों से निकलने वाली नदियों में ढलान होने के कारण कम गहराई में खनन होना चाहिए जबकि नदी के स्तर समतल होने पर अधिक गहराई से खनन होना चाहिए। उनके द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि नदी के बीचोंबीच गहराई तक खनन होना चाहिए, जिससे नदी का बहाव बीच में होगा, जिससे कटाव तथा बाढ़ का खतरा नहीं होगा। भूमि कटाव रोकने हेतु खनन कार्य अनिवार्य है। खनन कार्य होने से खनिज के दामों में भी कमी आयेगी तथा राज्य सरकार को राजस्व प्राप्त होगा। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन का ठेका किसी व्यक्ति विशेष को न देकर स्वयं गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा ही किया जाना चाहिए, जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिले, गरीब परिवारों को इसका लाभ मिले तथा क्षेत्रवासियों को सस्ती दरों पर खनन सामग्री का लाभ मिल सके।

2. श्री विरेन्द्र सिंह थापली (पूर्व जिला पंचायत सदस्य) निवासी सुद्धोवाला द्वारा कहा गया कि पर्यावरणीय स्वीकृति न मिलने से अवैध खनन किया जा रहा है। उनके द्वारा कहा गया कि हमारे गांव में 60 प्रतिशत लोग बेरोजगार हैं, यदि नदी में वैध खनन शुरू हो जाता है तो गरीब परिवारों को इसका लाभ मिलेगा, उनको रोजगार प्राप्त होगा तथा मकान, मन्दिर, धर्मशाला, सड़कों के निर्माण आदि के लिये बाहर से खनिज सामग्री नहीं मंगानी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त ट्रक, ट्राली, बुग्गी चलाने वालों को रोजगार प्राप्त होगा तथा सस्ती दरों पर खनन सामग्री प्राप्त होगी। अन्त में उनके द्वारा कहा गया कि गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा ही खनन किया जाना चाहिए।
3. ज्ञानचन्द निवासी सुद्धोवाला द्वारा पूछा गया कि खनन से स्थानीय गांव को क्या लाभ मिलेगा? एवं स्थानीय निवासियों को मकान आदि बनाने के लिये खनन सामग्री में छूट हेतु क्या प्राविधान है?
4. धमेन्द्र, निवासी सुद्धोवाला खनन कार्य शुरू किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।
5. ओमप्रकाश, निवासी नंदा की चौकी द्वारा कहा गया कि बेरोजगारी से बहुत समस्याएं हो रही हैं, इसलिये खनन खुलना चाहिए। उनके द्वारा खनन कार्य वैध तरीके से किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।
अपर जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त खनन कार्य राज्य सरकार की भूमि से किया जायेगा एवं खनन का कार्य अग्रतर बोली के माध्यम से स्थानीय व्यक्तियों







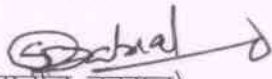
को प्राथमिकता दिये जाने का प्राविधान है। राज्य सरकार की खनन नीति के अनुसार खनन कार्य से प्राप्त लाभांश के 5 प्रतिशत भाग को खनिज विकास निधि के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों के विकास कार्यों में व्यय किया जायेगा। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा खनिज सामग्री में छूट दिये जाने की मांग के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीय निवासियों के भवन एवं सामाजिक कार्यों हेतु खनिज सामग्री में राज्य सरकार खनिज नीति में कोई प्राविधान नहीं है। ग्रामीण एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधि राज्य सरकार के स्तर पर खनिज सामग्री स्वयं के उपयोग हेतु छूट के प्राविधान की मांग कर सकते हैं।

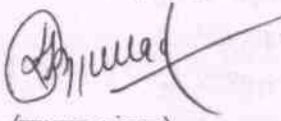
अन्त में उक्त आपत्तियों के अनुक्रम में जीएमवीएन के प्रतिनिधि द्वारा उपरोक्त सुझावों के अनुक्रम में अवगत कराया गया कि खनन कार्य राज्य सरकार की भूमि पर किया जाना है। किसी निजी भूमि पर खनन कार्य नहीं किया जायेगा। प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य सरकार की खनिज नीति के अनुसार स्थानीय निवासियों को खनिज पट्टे अन्तर्गत किये जाने की प्राथमिकता का प्राविधान है एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुसार कार्य किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीय ग्रामीणों के विकास हेतु कारपोरेट सोशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के अन्तर्गत खनन कार्य से प्राप्त लाभांश का कुछ भाग विभिन्न सामाजिक विकास कार्य में व्यय किये जाने का भी प्राविधान है। स्थानीय स्तर पर खनन कार्य होने से स्थानीय रोजगार उपलब्ध होना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा बताया गया कि खनन कार्य न होने के कारण नदी का वास्तविक स्वरूप बदल जायेगा और नदी जंगल एवं कृषि भूमि का कटाव करेगी इसलिये नदी का चुगान वैज्ञानिक तरीके से करना अति आवश्यक है। परियोजना के अन्तर्गत स्थानीय लोगों की सहभागिता का भी पूरा ध्यान रखा जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि खनन वैज्ञानिक तरीके से किया जाये जिससे पर्यावरणीय क्षति न हो। अन्त में सभा में उपस्थित व्यक्तियों द्वारा हाथ खड़े कर खनन कार्य हेतु सहमति व्यक्त की गयी।


तदोपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति के द्वारा समापन की घोषणा की गयी है। जन सुनवाई की कार्यवाही की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी की गयी है।

संलग्नक-

1. फोटो - 03
2. डी0वी0डी0 - 03
3. उपस्थिति पंजिका - 03


(सुनील डबराल)
अनु० सहा०


(सुभाष पंवार)
अ० अभियन्ता


26.8.11
(प्रताप सिंह शाह)
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
देहरादून

26 08 2014

हौंस नदी के लाट नं 3/10 में युगान / रानन हट्ट सिंक 26/08/2014
 प्रातः 11 बजे प्रातः सेक्टर नामलिप (नक प्रीकैप्चा (P.M.P.N) सुहावाला
 में हट्ट लोकमुनार्ड में स्थापित व्यक्तियों की स्थापिति पत्रिका:-

क्र	नाम व पद	पता	फोन नं	सहामत
1)	श्री. प्रताप सिंह शाह (Asst. Manager)	जिला पशुधन देहरादून	975666655	
2)	श्री. सुभाष पंत (Asst. Manager)	पट्टा निगाबोर्ड देहरादून	9416393598	
3)	श्री. सुलिल शर्मा (Asst. Manager)	पट्टा निगाबोर्ड देहरादून	9634237820	
4)	विवेक कुमार (Asst. Manager)	GRC Andhra Pradesh Warda.	8377078376	
5)	वर्गीस माथु (Asst. Manager)	GRC India Ltd. Warda	8860056978	
6)	विजय कुमार (Asst. Manager)	GRC Dehradun	9528553227	
7)	Bobby	सुधीवाल	9537912523	BS
8)	हरि सिंह	सुधीवाल	—	हरि सिंह
9)	लाला	सुधीवाल	—	LALA
10)	राजेश	सुधीवाल	—	राजेश

	नाम व पद	पता	फोन नं०	हस्ताक्षर
11	चंद्र पाल	मुन्डी बाला	—	चंद्र पाल
12	राम गोपाल	सुखेवाला	—	राम गोपाल
13	रवि कुमार	भाव बाला	—	रवि कुमार
14	जिनंद	मुन्डी बाला	—	जिनंद
15	जीवारी	सुखेवाला	—	जीवारी
16	व्यमेश्वर	भाव बाला	—	व्यमेश्वर
17	पाला	भाव बाला	—	पाला
18	जुगल विमारी	भाव बाला	—	जुगल विमारी
19	सौनवारी	सुखेवाला चौकी	—	सौनवारी
20	जोगेश्वर	गन्दा चौकी	—	जोगेश्वर
21	अगवानदास	गन्दा चौकी चौकी	—	अगवानदास
22	अजुनी	गन्दा चौकी चौकी	—	अजुनी
23	आम पुजारी राजा	गन्दा चौकी चौकी	—	आम पुजारी
24	राम प्रसाद	गन्दा चौकी चौकी	—	राम प्रसाद
25	रघुवीर	गन्दा चौकी चौकी	—	रघुवीर

30/12/2015

Sl. No.	Name	Address	Phone No.	Signature
26	विश्व नारायण उमराव	सुधीवाला	9319630637	Singh
27	S.S. Panwar	Sudhawal	9893077803	
28	सुधीवाला उमराव	सुधीवाला	—	राजेश
29	Anand Singh	"	9897079821	Singh
30	Rajesh Kumar	Sudhawal & सुधीवाला	9837294907	Raj
31	अमित		—	
32	मि. राजेश	सुधीवाला	—	Mit
33	Anand	सुधीवाला	—	
34	सतीश कुमार	सुधीवाला	9411361796	Satish
35	विश्वनाथ सिंह	सुधीवाला	—	Singh
36	विश्वनाथ सिंह	सुधीवाला	988776028	
37	विश्वनाथ सिंह	G.M.V.N. (F)	—	
38	B.S. Raina	G.M.V.N. (F)	70315105505	
39	राजेश	सुधीवाला	—	राजेश
40	सावन पुंडीर	सुधीवाला	—	

#0 गठवा
नं-31
दि-

52	0	नाम व पद	पता	सं-पुस्तक	डो
41		जगदीश राजवासी	कमलकवीरगाव	9612028849	सुंद
42		श्री M मंगल	खडोवाला	—	श्री M
43		राजीव शिंदे	आरकास गाव		श्री सुंद
44		निरंजन शिंदे	सुंदगाव	9897732856	सुंद
45		चंद्रशेखर शिंदे	सुंदगाव	941280397	सुंद
46		सुंदर सिंह शिंदे	कांठा गाव	9897340386	शिंदे
47		विष्णू शिंदे	दांढी	9012280350	शिंदे
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					